RASHTRIYA SAHARA, Delhi, 4.11.2020
Page No. 7, Size:(14.53)cms X (13.23)cms.

वापी से बड़ोदरा के बीच बुलेट ट्रेन के लिए रेल खंड का निर्माण शुरू

■ विनोद श्रीवास्तव

नई दिल्ली। एसएनबी

देश की अति महत्वाकांक्षी मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए जमीनी तौर पर रेल निर्माण को लेकर काम शुरू हो गया है। वापी से बड़ोदरा के बीच परियोजना के 47 प्रतिशत रेल खंड के डिजाइन और निर्माण का ठेका दे दिया गया है। हालांकि परियोजना पर काम शुरू करने के लिए अति महत्वपूर्ण भूमि अधिग्रहण अब तक शत-प्रतिशत पूरा नहीं हुआ है। गुजरात के हिस्से में भूमि अधिग्रहण 86 प्रतिशत हो गया है, लेकिन महाराष्ट्र के हिस्से में अभी भूमि अधिग्रहण केवल 22 प्रतिशत ही हो पाया है। हालांकि महाराष्ट्र सरकार ने भरोसा दिया है कि वह परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण जल्दी पूरा करके देगी।

इस संबंध में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन एवं सीईओ विनोद कुमार यादव ने बताया कि 508 किलोमीटर लंबी मुंबई-अहमदाबाद हाईस्पीड रेल परियोजना में से 237 किलोमीटर रेल खंड के डिजाइन और निर्माण का कार्य आवंटित कर दिया गया है। इस

महाराष्ट्र ने भरोसा दिया जल्दी पूरा किया जाएगा भूमि अधिग्रहण

गुजरात में 86 प्रतिशत और महाराष्ट्र में अब तक 22 प्रतिशत भूमि का ही हो सका है अधिग्रहण

निर्माण पर 24,985 करोड़ रुपये खर्च होंगे। यह क्षेत्र वापी से बड़ोदरा के बीच का है। इस रेल खंड पर चार स्टेशनों वापी, बिलमोरा, सूरत और भरुच का निर्माण होगा। हालांकि अभी परियोजना के 53 प्रतिशत रेल खंड के निर्माण का ठेका दिया जाना है, जो पाइपलाइन में है।

उन्होंने बताया कि परियोजना के लिए अभी 66 प्रतिशत भूमि का अधिग्रहण किया गया है, जिसमें 86 प्रतिशत भूमि गुजरात में और 22 प्रतिशत भूमि महाराष्ट्र में अधिग्रहित की गई है। लेकिन अगले महीने तक गुजरात में 95 प्रतिशत तक भूमि का अधिग्रहण कर लिया जाएगा और महाराष्ट्र में भूमि अधिग्रहण में तेजी आएगी। इस संबंध में महाराष्ट्र सरकार के अधिकारियों की ओर से भरोसा दिया गया है कि जल्दी ही वे परियोजना से संबंधित भूमि का अधिग्रहण पूरा कर लेंगे। उन्होंने बताया कि परियोजना का 75 प्रतिशत हिस्सा गुजरात में और 25 प्रतिशत हिस्सा महाराष्ट्र में है। लिहाजा हम जल्दी ही वहां भी परियोजना को अवार्ड कर देंगे। फिर जमीनी तौर कर कार्य शुरू हो जाएगा। इस परियोजना से रोजगार सृजन के साथ-साथ, निर्माण सामग्री व मशीनरी की आपूर्ति बड़ी मात्रा होगी। भारतीय कम्पनियों के निर्माण कराने के कारण कौशल विकास को भी बढ़ावा मिलेगा।